ई संदेश

07 मई, 2026 | अंक - 204

सात दिन, सात पृष्ठ

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों के उत्थान एवं समग्र विकास हेतु पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा सहित कई ऐतिहासिक योजनाओं का किया शिलान्यास
- मुख्यमंत्री जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के दिए कड़े निर्देश
- प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ इज़ाफ़ा ,मिशन रोजगार के तहत 609 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र
- पांच सौ नव चयनित लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबन्धन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई धार
- गोरखपुर को मिली 612 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात से आम जनमानस के जीवन में आएगा अभूतपूर्व बदलाव
- शिक्षामित्रों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदान की सामाजिक सुरक्षा की बड़ी सौगात
- गोरखपुर तारामंडल क्षेत्र में नवनिर्मित ब्रिज से कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिला अभूतपूर्व विस्तार
- प्रयागराज के नॉर्थ टेक सिम्पोज़ियम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रथम का मंत्र देकर आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को सराहा
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 04 मई, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों के उत्थान एवं समग्र विकास हेतु पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा सहित कई ऐतिहासिक योजनाओं का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 मई, 2026 को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस व बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 'श्रमवीर गौरव समारोह'-2026 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए भारत के वास्तविक शिल्पकार हमारे श्रमिक ही हैं और 'हर हाथ को काम' तथा 'हर श्रमिक को सम्मान' दिलाना सरकार का मुख्य संकल्प रहा। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में श्रमिक सुविधा केन्द्र तथा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रेटर नोएडा में 300 बेड के ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल के निर्माण हेतु 7.2 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, दसवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अटल आवासीय विद्यालय के 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को टेबलेट व प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले वाराणसी व प्रयागराज के अटल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया एवं 05 श्रमिकों को टूलकिट प्रदान कर उनका सम्मान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार नए वेज बोर्ड में ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों की भांति उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को भी 05 लाख रुपये के सुरक्षा बीमा कवर की सुविधा मिल सके। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को सुरक्षा, डॉर्मिटरी, आवासीय सुविधा, सस्ती कैंटीन, गुणवत्ता युक्त भोजन और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवास तथा औद्योगिक विकास विभाग को पॉलिसी बदलने के कड़े निर्देश दिए गए। उद्योगों के समीप ही श्रमिकों के लिए आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एफ0ए0आर0 में छूट प्रदान करने की बात भी कही गई। इसके साथ ही, बचे हुए सभी श्रमिकों को 'आयुष्मान भारत' के तहत प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये के निःशुल्क उपचार की सुविधा से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 01 करोड़ श्रमिक परिवार अर्थात 05 करोड़ लोग सीधे लाभान्वित होंगे।

श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु प्रदेश के शेष 34 जनपदों में एक-एक ई0एस0आई0सी0 औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया और गीडा गोरखपुर में भी ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल हेतु 05 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु लगातार नए प्रयास किए, जिसमें मजदूरी न मिलने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई से लेकर कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत बटाईदारों को मुआवजा देने जैसे निर्णय शामिल हैं। डबल इंजन सरकार ने श्रमिकों को हमेशा प्राथमिकता दी, जिसका प्रमाण कोरोना जैसी भयंकर त्रासदी के दौरान भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 09 वर्षों में किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में उद्योगों की संख्या 14,000 से बढ़कर 32,000 से अधिक हो गई, जिससे 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक के साथ-साथ श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर ने भी श्रमिकों के हित में उठाए गए इन ऐतिहासिक कदमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में श्रमिकों के अतुलनीय योगदान को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के दिए कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 मई, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आहूत 'स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन' की बैठक में प्रदेश की प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक पार्क और शहरी परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर कर परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास होने के दृष्टिगत चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की वित्तीय निविदा का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए।

चित्रकूट, फर्रुखाबाद और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन से अद्यतन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इन एक्सप्रेस-वे के लिए आगामी 31 मई तक 90 प्रतिशत भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने और आवश्यक रेट रिवीजन के प्रस्ताव तत्काल भेजने के निर्देश दिए, ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय 15 दिन बाद इसकी समीक्षा कर सके। भूमि-स्वामियों से सीधा संवाद कर उचित मुआवजा दिलाने और रजिस्ट्री हेतु अतिरिक्त मैनपावर तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी तथा मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भी कार्रवाई तेज करने को कहा गया।

राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण हेतु लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी होने पर मुख्यमंत्री जी ने इसके शिलान्यास की तैयारी के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब को लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परियोजनाएं प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगी। मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित करेगी। 75 जनपदों में 150 विद्यालयों के निर्माण की प्रगति पर उन्होंने विद्यालय स्थापना के लिए अच्छी लोकेशन को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल बनाकर शीघ्र लागू करने और औद्योगिक भूखण्डों पर तय समय-सीमा के भीतर उद्योग स्थापित करने के निर्देश दिए गए। निवेशकों से संवाद कर कार्यवाही आगे बढ़ाने और बायो एनर्जी व सी0बी0जी0 परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवाचार आधारित दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया। लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को रोजगार सृजन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हुए समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सी0एम0 ग्रिड योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे आधुनिक शहरी सड़कों के लिए अहम बताया और लखनऊ की वृन्दावन योजना में इण्टीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल परियोजना से नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलने की बात कही।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ इज़ाफ़ा ,मिशन रोजगार के तहत 609 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03 मई, 2026 को मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवचयनित 357 कनिष्ठ विश्लेषकों (औषधि) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नवचयनित 252 दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों को नियुक्ति पत्र प्रदान। नव चयनित अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि सरकार की स्पष्ट नीति और साफ नीयत के हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी का प्रतिफल है कि प्रदेश में अब तक 09 लाख से अधिक युवाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी प्रदान की गई है, जो देश के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं पूरी टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस चयन प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी को सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सरकार ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है, जहां वे ईमानदारी से अपना जीवन संवार सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में भारी भ्रष्टाचार होता रहा और प्रदेश गुण्डागर्दी व अराजकता का पर्याय बन गया। परन्तु वर्ष 2017 के बाद से चयन प्रक्रिया में भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। भर्ती में धांधली करने वालों के लिए सरकार ने आजीवन कारावास और सम्पत्ति जब्ती जैसे कठोर प्रावधान लागू किए हैं।

सुरक्षित भविष्य और रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार ने 02 लाख 20 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक सम्पन्न की है। हाल ही में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग पूरी कर उन्हें फील्ड ड्यूटी पर भेजा गया है। वर्ष 2026-27 में विभिन्न विभागों में डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जाति, मत या मजहब के आधार पर भेदभाव को महापाप बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विगत 09 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था और प्रतिव्यक्ति आय को तीन गुना करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।

स्वास्थ्य और औषधि प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज और दो एम्स जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। औषधि एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में हर मण्डल स्तर पर 'ए-ग्रेड' प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। पूर्व में पूरे राज्य में मात्र पांच प्रयोगशालाएं कार्यरत रहीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 18 हो गई है। कनिष्ठ विश्लेषकों की भर्ती से नमूनों की जांच क्षमता में भारी वृद्धि होगी और मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सकेगी। दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों की नियुक्ति को भी आम जनमानस के उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक कदम बताया गया।

रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप और एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में भी युवाओं को अपार संभावनाएं मिली हैं। प्रदेश के सुरक्षित वातावरण के कारण बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हो रहा है। हाल ही में फार्मा सेक्टर की 17 कम्पनियों को 'लेटर आफ कम्फर्ट' प्रदान किए गए, जिससे राज्य में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

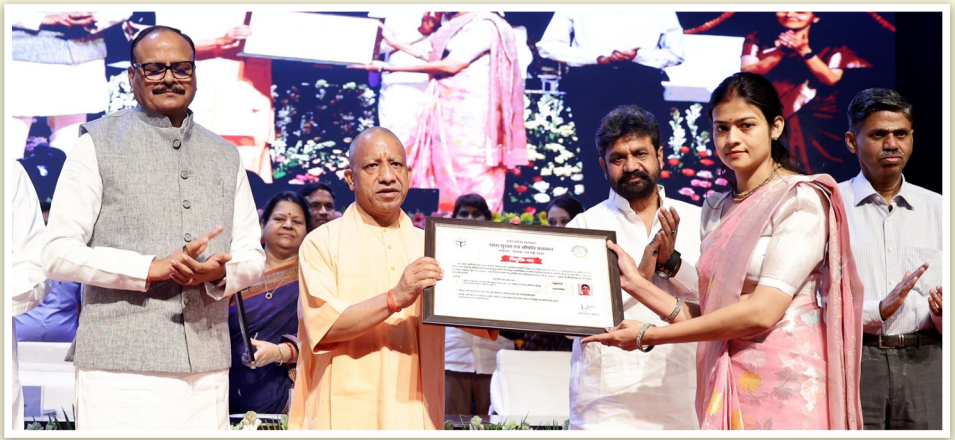

पांच सौ नव चयनित लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबन्धन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई धार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 मई, 2026 को लखनऊ के लोक भवन में मिशन रोजगार के अन्तर्गत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा विभाग के 371 तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के 129 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नव चयनित अभ्यर्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं की योग्यता को सम्मान देना तथा उन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना ही प्रदेश सरकार की असली कसौटी है। इस निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के हर जाति, क्षेत्र और सम्प्रदाय के योग्य युवाओं का चयन किया गया। पारदर्शी चयन प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि पंचायत लेखा परीक्षा विभाग में 78 तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में 25 बेटियों ने स्थान प्राप्त किया, जो इस क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते रुझान का सकारात्मक संकेत है। उन्होंने युवाओं को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ दायित्व निर्वहन का मन्त्र दिया। साथ ही याद दिलाया कि प्रदेश सरकार विगत 09 वर्षों में 09 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान कर चुकी है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले तथा भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख करते हुए नव चयनित परीक्षकों को बिना किसी लोभ-लालच के कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण संस्था होती है और सही तथ्यों पर आधारित ऑडिट से बेहतर वित्तीय प्रबन्धन व अनुशासन को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। यदि कोई गलत कार्य हुआ है तो उसे स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।

प्रदेश की आर्थिक प्रगति का खाका खींचते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में 03 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। प्रदेश की बेटियां ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के रूप में बेहतरीन काम कर रही हैं। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश को कोई बैंक ऋण देने को तैयार नहीं हुआ, परन्तु अब यह प्रदेश देश के टॉप थ्री राज्यों में शामिल होकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। इसी सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन का परिणाम है कि 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए किसी बैंक से कर्ज नहीं लेना पड़ा।

राज्य के ऋण को कम करने और अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में स्थानीय लेखा परीक्षकों की सराहनीय भूमिका को रेखांकित किया गया। वर्ष 2017 से पूर्व एक्साइज से मात्र 12 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जो अब बढ़कर 62-63 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगर पालिका व नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इन नव चयनित युवाओं की अहम भूमिका होगी। एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन से ही ग्राम पंचायत और नगर निगम जैसी बुनियादी इकाइयां आत्मनिर्भर व स्मार्ट बन सकेंगी।

गोरखपुर को मिली 612 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात से आम जनमानस के जीवन में आएगा अभूतपूर्व बदलाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05 मई, 2026 को गोरखपुर के माधवनगर, जंगल बेनीमाधव में 05 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कल्याण मण्डपम् (कन्वेंशन सेण्टर) के लोकार्पण सहित लगभग 612 करोड़ रुपये की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कल्याण मण्डपम् का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा इसके परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के मोहल्लों में सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए एक अत्याधुनिक कल्याण मण्डपम् प्राप्त हुआ। इसके सभागार में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई और ऊपरी मंजिल पर भी एक सभागार बनाया गया। सुविधाओं के लिए पांच-छह अटैच रूम अलग से निर्मित हुए।

क्षेत्रवासी इस कल्याण मण्डपम् के बड़े प्रांगण में आकर आसानी से बेटी की शादी, बच्चों का मुण्डन संस्कार, कोई बैठक या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न कर सकेंगे। अब यहां के लोगों को उनके मोहल्ले में ही यह सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। यह कल्याण मण्डपम् विधायक निधि और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से निर्मित हुआ। लोगों की विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए होटल, मैरिज लॉन या सड़क पर टेण्ट लगाने की निर्भरता खत्म हुई। इन विकास परियोजनाओं में 270 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण कार्य भी शामिल रहा। इस एक ही भवन में मण्डलायुक्त के कार्यालय के साथ-साथ मण्डल स्तर के सभी विभागों के अधिकारी बैठेंगे, जिससे जनता को सभी विभागों की सेवाएं एक ही जगह प्राप्त होंगी।

गरीब, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग सहित हर तबके के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 173 करोड़ रुपये की लागत से कुशमी एन्क्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना का शिलान्यास भी किया गया। इसके साथ ही गोरखपुर महानगर में आर0सी0सी0 नाला, सड़क कार्यों, सोनौली मार्ग पर प्रवेश द्वार के निर्माण और पथ-प्रकाश आदि सुविधाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। यह योजनाएं आम जनमानस की सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा उनके सपनों को नई उड़ान देने का एक सशक्त माध्यम बनीं। गोरखपुर महानगर में 09 कल्याण मण्डपम् का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से कई का लोकार्पण हो चुका और अन्य निर्माणाधीन हैं।

सरकार के सकारात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 के पहले कोई नहीं सोचता था कि गोरखपुर का बन्द खाद कारखाना पुनः संचालित होगा, जो अब पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। बरगदवा से नकहा होते हुए मोहद्दीपुर तक 4-लेन सड़क बन गई। पहले गोरखपुर से लखनऊ जाने में 08 से 09 घण्टे लगते रहे, परन्तु अब यह दूरी मात्र तीन से साढ़े तीन घण्टे में तय होने लगी। गोरखपुर से वाराणसी जाने का समय भी घटकर मात्र ढाई घण्टे रह गया। कुशीनगर जाने के लिए भी अब गोरखपुर शहर में जाने की आवश्यकता नहीं बची।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास की गति जितनी तेज होगी, व्यक्ति और समाज की समृद्धि भी उतनी ही तेज होगी। इसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर का निरन्तर विस्तार किया गया। एम्स तथा बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज बेहतर तरीके से काम करने लगे और आयुष विश्वविद्यालय भी बन गया। सरकार ने गोरखपुर की पुरानी छवि को पूरी तरह बदल दिया। जहाँ पहले गोरखपुर की पहचान मच्छर और माफिया से होती रही, वहीं अब दोनों गायब हो चुके हैं। अब गोरखपुर की पहचान सुरक्षा, स्वच्छता, अच्छी सड़कों तथा समृद्धि से स्थापित हुई। सरकार ने साफ नीयत, स्पष्ट नीति तथा दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करके विकास के बेहतरीन परिणाम प्रस्तुत किए।

शिक्षामित्रों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदान की सामाजिक सुरक्षा की बड़ी सौगात

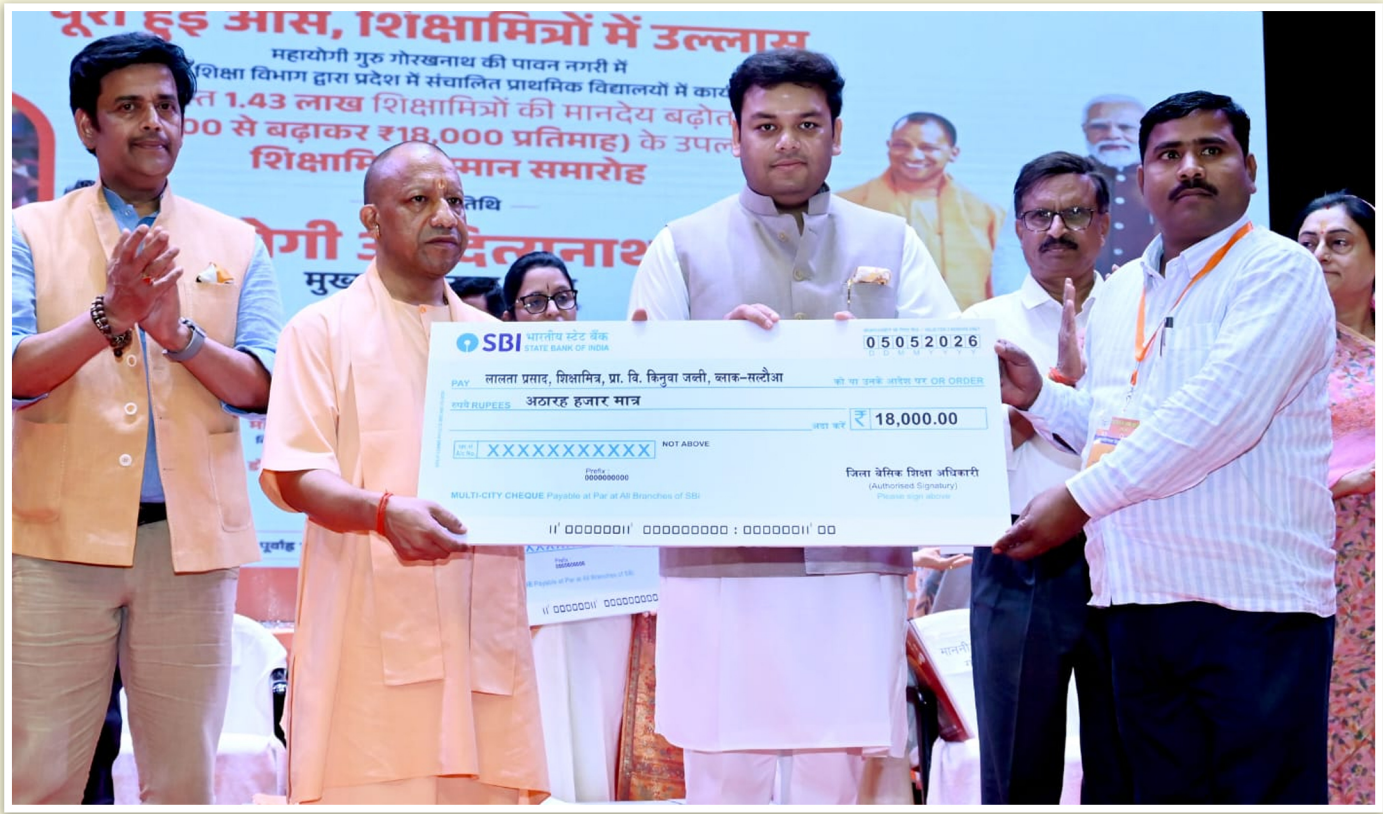

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05 मई, 2026 को जनपद गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 'शिक्षामित्र सम्मान समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 01 लाख 43 हजार शिक्षामित्रों के मानदेय में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी (10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह) के उपलक्ष्य में अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री जी ने चयनित शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए और सामर्थ्यवान भारत का उदय हुआ। देश मजबूती के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर रहा। विकास के इस दौर में नींव के पत्थर के रूप में बेसिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने शिक्षामित्रों से कहा कि जितनी मजबूत नींव आप तैयार करेंगे, राष्ट्र का भवन उतना ही सशक्त स्वरूप लेगा। विगत 09 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए।

मुख्यमंत्री जी के अनुसार, वर्तमान समय सकारात्मक सोच का रहा। यदि शिक्षा जगत से जुड़ा व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेगा, तो समाज के पुण्य की बड़ी क्षति निश्चित रही। उन्होंने जोर दिया कि अभिभावक जिन बच्चों को बड़े विश्वास के साथ विद्यालय भेजते हैं, उनका भविष्य संवारना शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति ही बेहतर परिणाम दे पाया, जबकि नकारात्मकता केवल विनाश का मार्ग प्रशस्त करती रही।

मुख्यमंत्री जी ने 'राष्ट्र प्रथम' के भाव पर बल देते हुए कहा कि पहले देश सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अच्छी पीढ़ी का निर्माण होने पर ही समाज को श्रेष्ठ शिक्षक, चिकित्सक, उद्यमी और नौकरशाह मिल पाए। उन्होंने शिक्षामित्रों को ट्रेड यूनियन जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि अतीत में ऐसी प्रवृत्तियों ने समाज को केवल नुकसान पहुँचाया। उन्होंने साफ कहा कि देश की कीमत पर कोई भी मांग पूर्ण नहीं की जा सकती।

पिछली सरकारों के रवैये की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती शासन के कारण शिक्षामित्रों के परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराए। उनकी सेवा समाप्ति का खतरा बना रहा, किंतु वर्तमान प्रदेश सरकार ने उनकी सेवाएं जारी रखते हुए सहयोग का संकल्प लिया। वर्ष 2017 में मानदेय को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया, जिसे अब बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, शिक्षामित्रों को 05 लाख रुपये का वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य कवर देने का निर्णय भी लिया गया, जिसकी सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि शिक्षामित्रों का मानदेय सीधे बैंक खातों में भेजा जाए, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवर का लाभ सुलभ हो सके। उन्होंने महिला शिक्षामित्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था पर तत्काल निर्णय लेने और उन्हें निवास के निकटतम विद्यालयों में तैनात करने की बात कही।

'ऑपरेशन कायाकल्प' की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, पेयजल और फर्नीचर जैसी सुविधाओं का सेचुरेशन 99 प्रतिशत तक पहुँचा, जो पहले मात्र 30-36 प्रतिशत रहा। ड्रॉप आउट रेट 19 फीसदी से घटकर केवल 03 प्रतिशत रह गया, जिसे शून्य करने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि सरकार 01 करोड़ 60 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग और स्वेटर आदि उपलब्ध करा रही रही। कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों को 12वीं तक उन्नत किया गया और जहाँ आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहाँ नए निर्माण की व्यवस्था की गई।

अंत में, मुख्यमंत्री जी ने 'स्कूल चलो अभियान' के तहत हुए 20 लाख नए नामांकनों की सराहना की और शिक्षकों से आगामी जुलाई में पुनः अभियान चलाकर प्रत्येक शिक्षक द्वारा 25-25 घरों का भ्रमण करने का आह्वान किया। उन्होंने बच्चों को स्नेहपूर्ण व्यवहार और रोचक कहानियों के माध्यम से शिक्षित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया कि समस्त शिक्षामित्र पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे।

गोरखपुर तारामंडल क्षेत्र में नवनिर्मित ब्रिज से कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिला अभूतपूर्व विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05 मई, 2026 को गोरखपुर के तारामण्डल क्षेत्र में वॉटर बॉडी के ऊपर गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 14 करोड़ रुपये से अधिक लागत से निर्मित 02-लेन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व में लोगों को इस क्षेत्र से जाने के लिए गोरखपुर-देवरिया बाईपास मार्ग से होकर जाना पड़ता रहा। पहले इस क्षेत्र से कनेक्टिविटी के बहुत कम माध्यम उपलब्ध रहे, लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने यहां इन्टरनल कनेक्टिविटी के लिये नये ब्रिज के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का शानदार विकास किया। 02-लेन ब्रिज के निर्माण से यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई और इस ब्रिज ने रामगढ़ताल क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में गोरखपुर की सबसे महंगी जमीन इस तारामण्डल और इसके आसपास के क्षेत्र की हो गई। यह गोरखपुर की सबसे पॉश कॉलोनी के रूप में उभर कर सामने आई। इस क्षेत्र ने समृद्धि के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। रामगढ़ ताल पर्यटन का बेहतरीन केन्द्र बन गया। इसके बगल में जू का निर्माण हुआ। यहां आसपास होटल, कन्वेंशन सेन्टर तथा साइंस पार्क आकार ले रहे। महन्त दिग्विजयनाथ पार्क और चम्पा देवी पार्क का नवनिर्माण भी प्रगति पर रहा। ताल के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हुआ। साथ ही, तारामण्डल का नए सिरे से पुनरुद्धार किया गया। यहां पर वॉटर बॉडी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। विगत 20 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में कोई रहने का साहस नहीं करता रहा। सन् 1998-99 में जब गोरखपुर में बाढ़ आयी, तो लोग पलायन कर गए। यहां पर एक ओर रामगढ़ ताल की गन्दगी और दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव रहा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण को यहां स्थित वॉटर बॉडी को पुनर्जीवित करने के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए। यहां के वॉटर लेवल को रामगढ़ ताल के वॉटर लेवल के समकक्ष जोड़कर देखने का प्रयास किया गया। प्रशासन को ऐसा प्लान तैयार करने को कहा गया जिससे कि यहां पर पानी बहता हुआ दिखाई दे और एक जगह जमा न हो। साथ ही, इसमें नौकायन की सुविधा भी विकसित की गई। बच्चे परिवार के साथ आकर खेलने, मनोरंजन करने तथा टहलने की अच्छी सुविधा का आनंद ले सके, ऐसा प्रबंध किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में यदि कोई गोरखपुर आया, तो वह यहां के विकास को देखकर अचम्भित तथा प्रफुल्लित हो उठा। यहां बेहतरीन कनेक्टिविटी का विकास हुआ। जब भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ, तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहा और जब उत्तर प्रदेश ने प्रगति की, तो गोरखपुर भी पीछे नहीं रहा। यहां चारों ओर से 04-लेन और 06-लेन की कनेक्टिविटी का विकास हुआ। एयरपोर्ट में नए सिविल टर्मिनल के निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ी। गोरखपुर एम्स में बेहतरीन सुविधाओं का विकास हुआ। अच्छे शिक्षण संस्थानों का निर्माण सम्पन्न हुआ। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना तथा पिपराईच की चीनी मिल फिर से चालू हो गई। आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूर्ण हुआ।

मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में विकसित हो रही सुविधाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। इस बदलते परिवेश में गोरखपुरवासियों को लम्बे समय तक इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये उन्होंने सुविधाओं को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। यहां अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की गई। इन लाइटों को चोरी करने तथा क्षति पहुंचाने वाले कारकों से सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी बनी। सुरक्षा के दृष्टिगत लगाई गई रेलिंग तथा सुन्दरीकरण कार्यों का संरक्षण करने की अपील की गई। एक साथ सामुदायिक भाव से किसी अभियान का हिस्सा बनने पर हमेशा बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री जी ने स्मरण कराया कि वर्ष 2017 से पहले गोरखपुर में सुरक्षा का भारी अभाव रहा। लोग माफिया और मच्छर से परेशान रहे। गोरखपुर का नाम सुनकर लोग डर जाते रहे। यहां कोई निवेश करने नहीं आता रहा। युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज रहा और उसे पहचान छुपानी पड़ी। युवाओं को नौकरी के लिए देश भर में भटकना पड़ा। वर्तमान में यहां के युवाओं को भटकने तथा पहचान छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। गोरखपुर के गीडा में लगे उद्योगों के माध्यम से गोरखपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार की सुविधा तथा नौकरी मिली। रामगढ़ ताल सहित प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया विकास देखने को मिला।

मुख्यमंत्री जी ने अपने मोहल्ले को साफ-सुथरा रखने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर बल दिया। मोहल्ले को साफ-सुथरा तथा सुन्दर बनाए रखने और अपना योगदान देने की बात कही गई। इन सभी कार्यों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ाने से बेहतर परिणाम सामने आए। अब तारामण्डल और उसके आसपास का क्षेत्र लोगों के आकर्षण का भारी केन्द्र बन गया। इसे मेन्टेन करके और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता जताई गई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भी लोग इसी प्रकार शासन की विकासपरक योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करते रहेंगे।

प्रयागराज के नॉर्थ टेक सिम्पोज़ियम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रथम का मंत्र देकर आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को सराहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 मई, 2026 को प्रयागराज में 'रक्षा त्रिवेणी संगम' की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिम्पोज़ियम (एन0टी0एस0)-2026 के समापन समारोह में 'नेशन फर्स्ट' के संकल्प को प्रत्येक भारतीय का जीवन मंत्र बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता और सियाचिन की ठंड से लेकर तपते रेगिस्तान तक सजग रहने वाले हमारे सैनिकों की सतर्कता के कारण ही पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित करते हुए सुरक्षित राष्ट्र को ही समृद्ध राष्ट्र की पहचान माना। उन्होंने उदारता की रक्षा के लिए शक्ति और सामर्थ्य को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि शांति की भाषा वही बोल सकता है जिसके पास पर्याप्त सामर्थ्य मौजूद हो। युद्ध के बदलते स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अब लड़ाई केवल जल, थल और नभ तक सीमित न रहकर साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर गई। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उदाहरण देते हुए की-बोर्ड को आधुनिक हथियार की संज्ञा दी और नेटवर्क सुरक्षा को नई रक्षा रेखा माना।

भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर तेजी से अग्रसर हुआ। कुछ वर्ष पहले तक मात्र 600 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाला भारत अब 50 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करने की सामर्थ्य विकसित कर चुका। भारत ने अपने मित्र देशों को भी सफलतापूर्वक सैन्य सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर दिया।

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट जैसे रणनीतिक नोड्स में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे। अलीगढ़ नोड छोटे हथियारों के केंद्र के रूप में उभरा और कानपुर गोला-बारूद तथा मिसाइल निर्माण का प्रमुख बिंदु बना। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण से सेना को नेक्स्ट जेनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को प्रदेश के बेहतरीन ईको-सिस्टम का आधार माना, जिससे निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के कारण ही कोई भी माफिया या बाहरी तत्व प्रदेश की प्रगति में हस्तक्षेप नहीं कर सका। उन्होंने आई0आई0टी0 कानपुर के साथ मिलकर विकसित किए जा रहे ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और तकनीकी विस्तार पर भी विशेष बल दिया। अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सशक्त समन्वय से उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने में निर्णायक भूमिका में सामने आया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 04 मई, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

● मंत्रिपरिषद ने वन ट्रिलियन डॉलर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम (OTD सी0एम0 फेलो) के संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में नवीन तकनीकी ज्ञान/पाठ्यक्रमों को समाविष्ट कर उद्योग जगत की वर्तमान एवं भावी तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने 150 राजकीय विद्यालयों में नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लिमिटेड (टाटा उद्यम) के सहयोग से DREAM (Design, Robotics, Electronics, Additive, Manufacturing) Skill Labs की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की है। यह स्थानान्तरण नीति केवल वर्ष 2026-27 के लिए है। स्थानान्तरण 31 मई, 2026 तक किये जाएंगे।

● मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अधिसूचित उत्तर प्रदेश ई-साक्ष्य प्रबन्धन नियम-2026, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका (निर्गतीकरण, तामीला तथा निष्पादन) नियम-2026 तथा उत्तर प्रदेश सामुदायिक सेवा गाइडलाइंस-2026 से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए उक्त को अनुमोदित कर दिया है।

● मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ पौधरोपण हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/मा0 उच्च न्यायालय परिसरों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियां/निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं/भारत सरकार के विभाग एवं उपक्रम/स्थानीय निकायों यथा-ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, प्राधिकरण आदि/रेलवे/रक्षा/औद्योगिक इकाइयों/सहकारी समितियों तथा अन्य को सम्बन्धित शासकीय विभागों/संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्यजीव विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध (यूकेलिप्टस एवं पॉपलर को छोड़कर) उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0 द्वारा निर्मित होने वाली 765/400/220/132 के0वी0 पारेषण लाइनों में लगाए जाने वाले विभिन्न टावरों हेतु कृषकों/भू-स्वामियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अंगीकृत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के अन्तर्गत टावर बेस के नीचे 200 प्रतिशत क्षेत्रफल (चारों तरफ 01 मीटर अतिरिक्त के अनुसार) एवं राइट ऑफ वे के कॉरिडोर के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल भूमि मुआवजे की लागत की गणना, उस क्षेत्र विशेष के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार की जाएगी।

● मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्ड पीठ लखनऊ में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रूप से संचालन हेतु मा0 न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 लॉ क्लर्क (ट्रेनी)/रिसर्च एसोसिएट के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क (ट्रेनी)/रिसर्च एसोसिएट का कार्यकाल 02 वर्ष के स्थान पर अधिकतम 03 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में अमरदीप विश्वविद्यालय फिरोजाबाद की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट, फिरोजाबाद को कतिपय शर्तों तथा अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत आशय-पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड की जनपद अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर तथा बिजनौर स्थित निष्प्रयोज्य पड़ी 04 मिलों की कुल 251.805 एकड़ भूमि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने झांसी जल संस्थान, झांसी द्वारा झांसी बबीना पेयजल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में की गई जलापूर्ति के मद में 30प्र0 जल निगम (नगरीय) को देय जल मूल्य की बकाया धनराशि 17.65 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर में केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु मौजा रामपुर तप्पा चौरा बड़गाँव परगना सि0जो0 तहसील, तहसील-पडरौना में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के बगल स्थित गाटा संख्या-473/1.054 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेख में सीलिंग खाते की भूमि दर्ज है तथा पडरौना-कुबेरस्थान मुख्य मार्ग से 500 मीटर दक्षिण स्थित है, में से 0.405 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने यमुना एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथॉरिटी क्षेत्र में अनुमानित लागत 653.53 करोड़ रुपये की 400/220 के0वी0, 3x500 एम0वी0ए0 जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सेक्टर-28 यीडा (गौतमबुद्धनगर) तथा सम्बन्धित लाइनों व 'बे' सहित निर्माण परियोजना को, 30प्र0 विद्युत नियामक आयोग के प्राविधानों के अनुरूप, टैरिफ बेस्ड कॉम्पटीटिव बिडिंग (टी0बी0सी0बी0) मोड से कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

● मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी0एम0 मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक 6-लेन में निर्माण (लम्बाई 14.280 कि0मी0) तथा आई0आई0एम0 लखनऊ से आउटर रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई 8.700 कि0मी0) के 2-लेन चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कार्य की सम्पूर्ण परियोजना एवं पुनरीक्षित लागत 546 करोड़ 51 लाख 83 हजार रुपये के व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना पी0एम0 मित्र पार्क को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर औद्योगिक विकास एवं यातायात सुविधा को बढ़ावा देगी।

● मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग में कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निविदाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अनुसार विभाग में कार्यों की गुणवत्ता में सुधार एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकने हेतु 05 करोड़ रुपये से अधिक लागत हेतु एस0बी0डी0 तथा 05 करोड़ रुपये से कम लागत हेतु टी-1 एवं टी-2 के माध्यम से प्राप्त होने वाली निविदाओं में कम लागत के आधार पर प्राप्त निविदाओं में अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी निविदादाताओं से जमा कराए जाने का प्रस्ताव है।

● मंत्रिपरिषद ने पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित